Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

अप्रैल 2023

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **4**

➢ ई-ऑक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ग्रेफाईट ब्लॉक का सफल आवंटन 4

➢ मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन 'रेडियो संगवारी' 4

➢ नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाएंगे 10-10 हज़ार रुपए 5

➢ छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 5

➢ मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेरोज़गारी भत्ता योजना की शुरूआत की 6

➢ प्रदेश के तीन और अस्पतालों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र 7

➢ अब केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी रबर की खेती 8

➢ 'अंगना म शिक्षा' कार्यक्रम को मिला 'स्कॉच अवार्ड' 8

➢ 'रैली फॉर रिवर्स' अभियान द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' की सराहना 9

➢ ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 10

➢ 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी 10

➢ छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 11

➢ प्रदेश में एक्सोटिक मांगूर एवं बिग हेड मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध 12

➢ 15 साल की चंद्रकला बनी गोल्डन बुक गर्ल 13

➢ केंद्रीय गृहमंत्री ट्रॉफी के सम्मान लिये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (P.T.S.) माना का चयन 13

➢ छत्तीसगढ़ में रबी फसलों की लक्ष्य से अधिक बोनी 13

➢ बीमार एवं बंद उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू 14

➢ नये कलेवर में वेब मीडिया 'सीजीवालडॉटकॉम' का शुभारंभ 15

➢ जल जीवन मिशन: राज्य में 21.20 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन 15

नोट :

- मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना'का किया शुभारंभ 16
- पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित 17
- उप स्वास्थ्य केंद्र खजुरी को प्रदेश भर में मिला प्रथम स्थान 17
- कायाकल्प योजना के अंतर्गत सूरजपुर ज़िले को मिला प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार 18
- मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले का सीएचसी जनकपुर स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन में प्रदेश में अव्वल 18
- कबीरधाम ज़िले के पाँच स्वास्थ्य संस्थानों को मिला कायाकल्प पुरस्कार 19
- केरता शक्कर कारखाना के नवनिर्मित को-जनरेशन पॉवर प्लांट का शुभारंभ 19
- राष्ट्रपति ने प्रदेश के दो पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया 20
- राज्य फाइनल: वर्ड पावर चैंपियनशिप -2023 20
- मुख्यमंत्री ने किया हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण 21
- मुख्यमंत्री ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि' योजना का शुभारंभ किया 21
- मुख्यमंत्री ने 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों को 4.40 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की 22
- शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर के 41 अस्पतालों को मान्यता 23
- मानस मंडलियों की महिलाओं को मिलेगा माता कौशल्या अलंकरण 23
- महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'स्टेट्स ऑफ वूमेन' पुस्तक का किया विमोचन 23
- खनिजों से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिला रिकार्ड 12 हज़ार 941 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व 24
- छत्तीसगढ़ मास्टर्स टेबल टेनिस टीम की घोषणा 24
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उल्लेखनीय कार्य के लिये छत्तीसगढ़ हुआ पुरस्कृत 25
- पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना का शुभारंभ 26
- छत्तीसगढ़ के पहले ज़ीरो वेस्ट, अत्याधुनिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण 26
- मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तक का किया विमोचन 27

नोट :

छत्तीसगढ़

ई-ऑक्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ग्रेफाईट ब्लॉक का सफल आवंटन

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा बलरामपुर ज़िला स्थित केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक को ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में सफल आवंटन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा केनापारा ग्रेफाईट ब्लॉक को ई-नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में आवंटन हेतु मेसर्स माँ कुदारगढ़ी स्टील्स प्रा. लि. द्वारा 111.00 प्रतिशत की अधिकतम बोली (फाइनल प्राईस ऑफर) लगाई गई। उक्त ब्लॉक को जीएसआई द्वारा जी-4 लेवल पर अन्वेषण किया गया था।
- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म जयप्रकाश मौर्य के निर्देशन में एमएसटीसी पोर्टल में 29 मार्च, 2023 को संचालित ई-नीलामी में कुल 670 बोली लगाई गई जिसमें मेसर्स माँ कुदारगदी स्टील्स प्रा. लि. द्वारा 111.00 प्रतिशत अधिकतम बोली लगाई गई।
- गौरतलब है कि राज्य द्वारा प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई-नीलामी की गई है। इसके पहले देश में केवल ओड़िशा एवं मध्य प्रदेश द्वारा ही ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया गया है।
- ग्रेफाइट रिफेक्ट्री, बैटरी, ल्युब्रिकेंट, क्रुसीबुल निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण खनिज है। वर्तमान में इसके ओडिशा एवं झारखंड में ही प्रमुख खानें हैं।
- संयुक्त संचालक एवं इंचार्ज ऑक्शन अनुराग दीवान ने बताया कि ई-नीलामी पद्धति से खानों का आवंटन पारदर्शिता एवं राज्य शासन को राजस्व में भागीदारी के उद्देश्य से अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है।
- छत्तीसगढ़ खनिज विभाग द्वारा अब तक इस प्रकार से चूना-पत्थर, बाक्साईट, लौह अयस्क, स्वर्णधातु एवं निकल, क्रोमियम एवं पीजीई तथा ग्रेफाइट के कुल 28 खनिज ब्लॉकों का सफलतापूर्वक आवंटन किया जा चुका है जिनसे आने वाले वर्षों में रायल्टी, डीएमएफ, पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर के अतिरिक्त लगभग 81 हज़ार करोड़ की अतिरिक्त आय राज्य शासन को होगी।

मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन 'रेडियो संगवारी'

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन 'रेडियो संगवारी'को लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में 'कका जिन्दा हे'छत्तीसगढ़ी गीत आडियो का विमोचन किया। इसके रचयिता प्रधान आरक्षक दिलीप ताम्रकार हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो संगवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला, लोक संस्कृति और गीत-संगीत को आम लोगों तक डिजिटल रेडियो स्टेशन के माध्यम से पहुँचाने के लिये इसकी स्थापना की गई है।
- छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एप के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों तक पहुँचाया जाएगा, निश्चित रूप से यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लुप्त हो रही सांस्कृतिक विधाओं और कला परंपराओं को नया जीवन देने के लिये यह प्लेटफार्म एक ताकतवर माध्यम हो सकता है। नये कलाकारों की प्रतिभाओं को भी इसके माध्यम से आसानी से दुनिया के सामने लाया जा सकता है।

नोट :

- रेडियो की श्रोताओं की आज भी कमी नहीं है। अपने नवाचारों और अपनी नयी सोच के कारण बहुत से रेडियो स्टेशन आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रेडियो संगवारी द्वारा शुरू किया जा रहा डिजिटल रेडियो स्टेशन भी ऐसा ही लोकप्रिय माध्यम बनेगा।
- इस अवसर पर रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा तथा सह-संस्थापक डॉ. हेमंत सिरमौर ने बताया कि रेडियो संगवारी को टू-जी इंटरनेट स्पीड पर भी आराम से सुना जा सकता है।

नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाएंगे 10-10 हज़ार रुपए

चर्चा में क्यों ?

2 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम निकुम में स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव में नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 हज़ार रुपए देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर उन्होंने पद्मश्री डोमार सिंह कुँवर और दीपक तारम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा मंच में 'चेत करो तन के' पुस्तक का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कला जगत के पुरोधा स्वर्गीय डॉ. रामचंद्र देशमुख ने राज्य की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने नाचा कलाकारों को नए ढंग से प्रशिक्षण देकर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश में अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया।
- विदित है कि ग्राम निकुम में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तीन दिवसीय स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा महोत्सव का आयोजन किया गया।
- छत्तीसगढ़ अंचल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत तथा कला जगत के धूमकेतु की उपमा से विभूषित दाऊ रामचंद्र देशमुख ने अपनी लोककला, लोकगीत के माध्यम से शोषण और अभावों से जूझती छत्तीसगढ़ी समाज को जागृत करने के लिये सार्थक पहल की। छत्तीसगढ़ अंचल के अभावग्रस्त जीवन एवं पीड़ा ने उन्हें इतना मर्माहत किया कि यही उनकी सभी प्रस्तुतियों का मूल स्वर बन गया।
- सन् 1951 में उन्होंने 'देहाती कला मंच' की स्थापना की। सन् 1971 में उन्होंने 'चंदैनी गोंदा' नाट्य पार्टी का निर्माण किया। चंदैनी गोंदा के बाद पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी की कहानी 'कारी' को 1983 में अभिनित किया गया जिसने अंचल में धूम मचा दी।

छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के निवास कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक महत्त्वपूर्ण अभियान 'छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023' कार्य का शुभारंभ सर्वेक्षण दल को हरी झंडी दिखाकर किया।

प्रमुख बिंदु

- सर्वेक्षण का कार्य पूरे प्रदेश में एक अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। इसके तहत सर्वेक्षण दल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य करेंगे।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 'छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023' नई-नई योजनाओं को बनाने और उनका बेहतर क्रियान्वयन कर लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य विगत वर्षों में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का आमजन के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नई योजनाओं के निर्माण के लिये उपयोग किया जाना है।
- सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही भी अब नवीन सूची में शामिल हो पाएंगे और उन्हें पात्रता के अनुसार शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बेरोज़गारी भत्ता योजना की शुरूआत की

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से महत्त्वकांक्षी बेरोज़गारी भत्ता योजना की प्रदेशव्यापी शुरूआत की। योजना की शुरूआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने चार युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा साथ ही बेरोज़गारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोज़गार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी।
- पात्रता की शर्तें:
  - बेरोज़गारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  - योजना के लिये आवेदन किये जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल की तिथि पर आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  - आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िला रोज़गार एवं स्वरोज़गार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेंडरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोज़गार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो।
  - आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो।
  - पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र बेरोज़गारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।
- कौन होगा अपात्र:
  - बेरोज़गारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोज़गार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र बनाया जाएगा। उम्र और रोज़गार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र बनाया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो।
  - आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोज़गार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिये अपात्र हो जाएगा।

- पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और ज़िला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हज़ार रुपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिये अपात्र होंगे।
- साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोज़गारी भत्ते के लिये अपात्र होंगे।

- बेरोज़गारी भत्ता का भुगतान : बेरोज़गारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोज़गार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रुपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- बेरोज़गारी भत्ता की अवधि : योजना के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता के लिये पात्र आवेदक को प्रथमतः एक वर्ष के लिये बेरोज़गारी भत्ता देय होगा। यदि हितग्राही विशेष को एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- कौशल प्रशिक्षण:
  - योजना अंतर्गत जिन आवेदकों को बेरोज़गारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें एक वर्ष की समयावधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा।
  - कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद आवेदक को रोज़गार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी।
  - आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आवेदक प्रशिक्षण लेने से इंकार करते है या ऑफर किया गया रोज़गार स्वीकार नहीं करते है तो उनका बेरोज़गारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

प्रदेश के तीन और अस्पतालों को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के तीन और स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत फरवरी माह में इन तीनों अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों के लिये उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। टीम ने इस संबंध में मरीजों से भी फीडबैक लिया था।
- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरगुजा जिले के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, महासमुंद के कोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कोरबा के गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाज़ा है।
- स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में गोपालपुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 89 प्रतिशत, कोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 85 प्रतिशत और सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 84 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है।
- इनमें उपलब्ध सेवाएँ, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

अब केरल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी होगी रबर की खेती

चर्चा में क्यों?

3 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा रबर अनुसंधान संस्थान कोटेयम (केरल) के मध्य एक समझौता किया गया है, जिसके तहत रबर अनुसंधान संस्थान, कोट्टायम छत्तीसगढ़ में रबर की खेती की संभावनाएँ तलाशने के लिये कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रायोगिक खेती करेगा।

प्रमुख बिंदु

- समझौता ज्ञापन पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक (अनुसंधान) डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी तथा रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टायम की संचालक (अनुसंधान) डॉ. एम.डी. जेस्सी ने हस्ताक्षर किये।
- इस समझौते के अनुसार रबर इंस्टीट्यूट कृषि अनुसंधान केंद्र बस्तर में एक हेक्टेयर रकबे में रबर की खेती हेतु सात वर्षों की अवधि के लिये पौध सामग्री, खाद-उर्वरक, दवाएँ तथा मज़दूरी पर होने वाला व्यय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराएगा। वह रबर की खेती के लिये आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन तथा रबर निकालने की तकनीक भी उपलब्ध कराएगा।
- पौध प्रबंधन का कार्य रबर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि रबर एक अधिक लाभ देने वाली फसल है। भारत में केरल, तमिलनाडु आदि दक्षिणी राज्यों में रबर की खेती ने किसानों को संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
- उन्होंने कहा कि रबर अनुसंधान संस्थान कोट्टायम के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की मिट्टी, आबोहवा, भू-पारिस्थितिकी आदि को रबर की खेती के लिये उपयुक्त पाया है और प्रायोगिक तौर पर एक हेक्टेयर क्षेत्र में रबर के पौधों का रोपण किया जाएगा। यहाँ रबर की खेती से किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त हो सकेगी।

'अंगना म शिक्षा' कार्यक्रम को मिला 'स्कॉच अवार्ड'

चर्चा में क्यों?

3 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला शिक्षिकाओं की पहल पर प्रारंभ किये गए 'अंगना में शिक्षा' कार्यक्रम को किसी स्वतंत्र संगठन द्वारा दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वर्ष 2022 के 'स्कॉच अवार्ड' से नवाज़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवार्ड के माध्यम से उन परियोजनाओं को सम्मानित किया जाता है, जो देश को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिये प्रयास करते हैं।
- 'अंगना म शिक्षा' को छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में पहुँचाए जाने हेतु कार्यक्रम डिजाइन कर क्रियान्वयन के लिये महिला शिक्षिकाओं की एक कोर टीम का गठन किया गया है, जिसमें सभी पाँच संभागों से प्रतिनिधित्व किया गया है।
- यह शिक्षिकाएँ विगत तीन वर्षों से इस कार्यक्रम की डिजाइन कर इसमें निरंतर सुधार लाने का प्रयास कर रही हैं। प्रत्येक गाँव में सबसे पहले 'अंगना म शिक्षा' मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय शिक्षिकाएँ समुदाय, आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं बड़ी कक्षाओं की बालिकाओं को शामिल किया जाता है।
- मेले में अलग-अलग काउंटर होते हैं, जिसमें माताएँ अपने बच्चों का आकलन करवाते हुए घर पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पर समझ बनाती हैं। मुख्य रूप से टेढ़े-मेढे लाईन पर चलना, चित्रों में रंग भरना, कागज से विभिन्न आकृतियाँ बनाना, वस्तुओं का वर्गीकरण करना एवं उन्हें क्रम से जमाना, कहानी सुनाना, चित्र देखकर उसका वर्णन करना, गिनती, मौखिक जोड़-घटाना जैसी गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है।
- मेले से सीखकर एवं शिक्षिकाओं द्वारा समय-समय पर उन्मुखीकरण करने से माताएँ बच्चों को घर पर सीखने में सहयोग देना प्रारंभ कर देती हैं।

नोट :

- इस कार्यक्रम में बेहतर और सक्रिय होकर कार्य कर रही माताओं को गाँव में पहचान दिलाने एवं उन्हें अन्य माताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु 'स्मार्ट माता' का खिताब देकर सम्मानित भी किया जाता है।
- स्मार्ट माताओं से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे अन्य माताओं को सक्रिय करते हुए स्कूल एवं आँगनबाड़ी में भी जाकर बच्चों की पढ़ाई में सुधार की दिशा में पहल करें।
- बच्चों को स्कूल में नए सत्र में प्रवेश के लिये जाते समय माताएँ अपने साथ एक सपोर्ट कार्ड भी लेकर जाती हैं, जिसमें वे बच्चों के दक्षता की वर्तमान स्थिति का आकलन कर स्वयं हस्ताक्षर कर यह सूचित करती है कि उन्होंने अपने बच्चों को इन दक्षताओं को हासिल करवा दिया है, अब इसके आगे सिखाने में सहयोग दें।
- आगामी सत्र में प्रवेश के पूर्व सभी गाँवों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगले चरण हेतु प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर महिला शिक्षिकाओं द्वारा तय किये जा रहे हैं। इस वर्ष 'अंगना म शिक्षा' दिवस एवं माताओं का अपने बच्चों के साथ सेल्फी लेने का भी प्रस्ताव है।

'रैली फॉर रिवर्स' अभियान द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' की सराहना

चर्चा में क्यों?

04 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ की गई 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' की सराहना 'रैली फॉर रिवर्स' अभियान द्वारा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- 'रैली फॉर रिवर्स' ईशा फाउंडेशन के सद्गुरू श्री जग्गी वासुदेव द्वारा देश की नदियों की दुर्दशा के बारे में जन-जागरूकता पैदा करने और शासन की नीतियों को नदियों के संरक्षण के उद्देश्य से बदलने के लिये लोगों का समर्थन प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया अभियान है।
- 'रैली फॉर रिवर्स' ने अपने ट्वीट के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किये गए इस योजना पर आधारित विज्ञापन को भी टैग किया है।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर 21 मार्च, 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया था।
- इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पाँच वर्षों में एक लाख 80 हज़ार एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। अब तक प्रदेश के 23 हज़ार 600 किसानों ने 36 हज़ार 230 एकड़ ज़मीन पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिये पंजीयन कराया है।
- इस योजना के माध्यम से किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हज़ार रुपए तक की आय होने का अनुमान है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को आमदनी होगी।
- इस योजना में पाँच एकड़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को शत-प्रतिशत अनुदान तथा पाँच एकड़ से अधिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।
- इस योजना का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध-शासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएँ, निजी शिक्षण संस्थाएँ, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं।
- 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना' में पहली बार चिन्हित प्रजातियों के वृक्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी भी दी गई है। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा।
- इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बाँस, टिश्यू कल्चर बंबू, रक्त चंदन, आँवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे।
- यह योजना हितग्राहियों के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वाईल हेल्थ की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण साबित होगी। इस योजना से काष्ठ आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2023 छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोज़गार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ में लागू नवीन औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता के परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिली है। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर निर्मित छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति 2019-24 निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही है। पिछले चार वर्षों में 2218 नवीन उद्योग स्थापित हुए जिनमें 21 हज़ार 457 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और 40 हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है।
- राज्य में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के तहत 600 करोड़ रुपए की लागत से 300 रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। साथ ही 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस नीति में छोटे निवेशकों को सेवा क्षेत्र में उद्यम के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे विकासखंडों जिनमें पारंपरिक रूप से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग प्रचलित है, उन्हें उच्च प्राथमिकता विकासखंड के रूप में वर्गीकृत कर सामान्य से अधिक अनुदान प्रदान किये जा रहे हैं।
- इस नीति के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक नहीं कि इकाई ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थापित हो। ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही शहरी क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रीयल पार्क की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है।
- राज्य की पारंपरिक कलाओं जैसे हैंडलूम वीविंग, मधुमक्खी पालन, लाख, जड़ी बुटी संग्रहण, बेल मेटल, ढोकरा शिल्प, बाँस शिल्प, गोबर एवं गौ मूत्र से बने उत्पाद, वनोपज से बने उत्पाद, अगरबत्ती, मोमबत्ती निर्माण, सिलाई, बुनाई इत्यादि को उच्च प्राथमिकता एवं प्राथमिकता निर्धारित कर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं।
- इस नीति के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने का प्रावधान है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि में ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी तथा भविष्य के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी।

'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत सहायता राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत सहायता राशि 25 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि इस वर्ष 2023-24 के लिये प्रस्तुत बजट में इस योजना के लिये 38 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इससे कई परिवारों का अपनी बेटियों का धूम-धाम से विवाह का सपना पूरा हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने योजना के तहत राशि में दो बार वृद्धि की है। भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रस्तुत पहले बजट में ही बेटियों के विवाह को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2019 में विवाह अंतर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 25 हज़ार रुपए कर दिया था। अब यह राशि बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए कर दी गई है।
- वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी 19 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए कर दी गई है। इससे कई परिवारों में बेटियों के विवाह को लेकर चिंता दूर हुई है।

- गौरतलब है कि कई परिवारों में आर्थिक परेशानियों के चलते बेटी का विवाह कठिन हो जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत बेटियों के विवाह के लिये सहायता करती है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह में होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना और सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से गरीब परिवार के आत्मसम्मान में वृद्धि के साथ उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना है।
- योजना तहत देय लाभ
  - योजनांतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार और 'मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना' अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है।
  - इसमें वर-वधु की श्रृंगार सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग के सामान उपहार स्वरूप प्रदान करने के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से रुपए भी दिये जाते हैं।
  - सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था के लिये भी कुछ राशि व्यय की जाती है।
  - योजनांतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है।
  - योजना का लाभ लेने के लिये ज़िला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ज़िला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। विकास खंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी या एकीकृत बाल विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। योजना के संबंध में अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं से भी जानकारी ली सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिये 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' लागू की है।

प्रमुख बिंदु

- इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता (ऋण) देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिला कार्यबल में वृद्धि होने के साथ ही उद्योग एवं व्यापार में उनकी सहभागिता बढ़ेगी। इस नीति से महिलाओं के द्वारा शुरू किये गए स्टार्टअप की संख्या में भी तेजी से इज़ाफा होगा।
- राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिये अधिकतम 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान रखा गया है।
- इस नीति के तहत महिला उद्यमियों द्वारा प्रदेश में स्थापित नवीन, विस्तारीकरण, शवलीकृत पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्य विनिर्माण व सेवा उद्यमों को आर्थिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

- उद्यम में किये गए स्थायी पूंजी निवेश का 30-55 प्रतिशत तक यानी 40 लाख से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, उद्यमों के लिये प्राप्त किये गए सावधि ऋण तथा परियोजना प्रतिवेदन में प्रावधानित कार्यशील पूंजी (अधिकतम तीन माह की आवश्यकता के बराबर) पर 45 से 70 प्रतिशत, अधिकतम राशि 15 से 60 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान, नए उद्यमों की स्थापना के लिये 50 प्रतिशत, अधिकतम 75 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दिनांक से 6 से 16 वर्षों तक, विद्युत शुल्क से छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 6 से 12 वर्षों तक पूर्ण छूट और उक्त के अतिरिक्त स्टांप शुल्क से छूट, परिवहन अनुदान, मंडी शुल्क से छूट, किराया अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- महिला स्व-सहायता समूहों को अतिरिक्त आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के रुप में अनुदानों में 5 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुदान और छूट के मामलों में 1 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि दी जाएगी।
- महिलाओं द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप उद्यमों को औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत घोषित स्टार्टअप पैकेज में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं छूट के मामलों में एक वर्ष अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये नई योजनाओं के निर्माण के साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दे रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योग में बड़ी संख्या में महिलाएँ काम कर रही हैं। इसके साथ ही स्व-सहायता समूह के माध्यम से गौठानों, वनोपज संग्रहण सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएँ राज्य के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

प्रदेश में एक्सोटिक मांगूर एवं बिग हेड मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, संवर्धन एवं पालन पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

6 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ शासन, मछलीपालन विभाग द्वारा प्रदेश में एक्सोटिक मांगूर (क्लेरियस गेरीपिनस) एवं बिग हेड (हाइपोप्थेलमिक्थीस नोबीलीस) मछलियों के मत्स्य बीज उत्पादन, मत्स्य बीज संवर्धन एवं पालन को प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन मछलियों का परिवहन, आयात एवं विपणन भी प्रतिबंधित किया गया है।
- इन प्रतिषिद्ध मछलियों का कोई भी मछुआ, वैयक्तिक, समूह या समिति, केंद्र या राज्य शासन द्वारा मत्स्यों का मत्स्य बीज उत्पादन, शासन अथवा वैयक्तिक जलस्रोत में संवर्धन एवं पालन नहीं करेगा।
- संचालक मछली पालन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र (संसोधन) अधिनियम 2015 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं 10 हज़ार रुपए अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- इन प्रतिबंधित मछलियों से संबंधित किसी भी गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर दोष सिद्ध उपरांत संबंधित को मत्स्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की योजनाओं से प्रतिबंधित भी किया जाएगा।

15 साल की चंद्रकला बनी गोल्डन बुक गर्ल

चर्चा में क्यों?

9 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ में दुर्ग के एक छोटे से गाँव पुरई की 15 साल की बेटी चंद्रकला ओझा लगातार आठ घंटे तक तैरकर विश्व कीर्तिमान रचते हुए गोल्डन बुक गर्ल बन गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस दौरान छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहे। इस कीर्तिमान की रिकॉर्डिंग भी की गई।
- विदित है कि मुख्यमंत्री ने दो दिन पहले ही पुरई गाँव में खेल अकादमी खोलने की घोषणा की थी। खास बात यह है कि देश भर में पुरई की पहचान खेल गाँव के तौर पर होती है। अब इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम के तौर पर भी जाना जाएगा।
- दुर्ग मुख्यालय से करीब 15 किमी. दूर स्थित पुरई गाँव की 15 साल की चंद्रकला ओझा ने बुलंद हौसलों के साथ गाँव के डोंगिया तालाब में रविवार 9 अप्रैल को सुबह 5 बजे से एक बजे तक पूरे आठ घंटे तक लगातार तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।
- गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के एशिया हेड मनीष विश्नोई ने बताया कि बिना ब्रेक के आठ घंटे पानी में लगातार तैरने का रिकार्ड किसी भी आयु वर्ग में अब तक नही था। चंद्रकला ओझा ने इसे कर दिखाया है। चंद्रकला को अब फाइनल सर्टीफिकेट दिया जाएगा। उसका यह रिकॉर्ड गोल्डन बुक में दर्ज किया जाएगा। जब भी दुनिया में कोई भी स्विमिंग का रिकॉर्ड सर्च किया जाएगा तो चंद्रकला का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा।

केंद्रीय गृहमंत्री ट्रॉफी के सम्मान लिये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (P.T.S.) माना का चयन

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (P.T.S.) माना का चयन केंद्रीय गृहमंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिये किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र के अनुसार सत्रावधि वर्ष 2021-2022 के लिये बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान हेतु राज्य के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माना को केंद्रीय गृहमंत्री ट्रॉफी के सम्मान के लिये चयन किया गया है।
- विदित है कि इससे पूर्व वर्ष 2019-20 और 2020-21 में इस ट्रॉफी के लिये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (P.T.S.) राजनांदगाँव का चयन किया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, राजनांदगाँव को नव आरक्षकों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिये यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दी गई थी।

छत्तीसगढ़ में रबी फसलों की लक्ष्य से अधिक बोनी

चर्चा में क्यों?

8 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस साल रबी के रकबे में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य हासिल करने के साथ ही 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी हो चुकी है, जो कि रबी सीजन के लिये निर्धारित लक्ष्य का 101 प्रतिशत है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बीते रबी सीजन में 18.30 लाख हेक्टेयर में खेती की गई थी। इस साल रबी रकबे में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही कुल 19.25 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 19.36 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई हो चुकी है, जो कि बीते साल रबी के रकबे से 5.77 प्रतिशत अधिक है।

नोट :

- राज्य में दलहन फसलों को प्रोत्साहन तथा समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के चलते किसानों का रूझान इसकी खेती की ओर काफी तेजी से बढ़ा है। चालू रबी सीजन में दलहन फसलों की बुआई 8.65 लाख हेक्टेयर में की जा रही है, जो कि इस साल रबी फसलों की खेती के लिये प्रस्तावित रकबे का 45 फीसदी है।
- छत्तीसगढ़ में अब तक अनाज की बोनी 5.97 लाख हेक्टेयर में, दलहन की बोनी 8.14 लाख हेक्टेयर में और तिलहन की बोनी 2.84 लाख हेक्टेयर में, गन्ना की 42 हज़ार 410 हेक्टेयर और साग-सब्जी एवं अन्य फसलों की लगभग 2 लाख हेक्टेयर हो चुकी है।
- राज्य में 2.71 लाख हेक्टेयर में गेहूँ, 1.71 लाख हेक्टेयर में मक्का, 35 हज़ार हेक्टेयर में रागी, 11 हज़ार हेक्टेयर में जौ-ज्वार एवं अन्य फसलें और 1.55 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज की बोनी पूरी कर ली गई है।
- इस प्रकार राज्य में 5.97 लाख हेक्टेयर में अनाज फसलों की बोनी पूरी कर ली गई है, जो कि रबी सीजन में अनाज फसलों की बोनी के लिये निर्धारित लक्ष्य 4.36 लाख हेक्टेयर का 137 प्रतिशत है।
- इस तरह दलहनी फसलों की बुआई 8.14 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जिसमें चना की 3.86 लाख हेक्टेयर में, मटर की 55 हज़ार हेक्टेयर में, मसूर की 34 हज़ार हेक्टेयर में, मूंग की 31 हज़ार हेक्टेयर में, उड़द की 27 हज़ार हेक्टेयर में, तिवड़ा की 2.50 लाख हेक्टेयर में, कुल्थी की 23 हज़ार हेक्टेयर में तथा अन्य दलहन फसलों की 7 हज़ार हेक्टेयर में बुआई पूरी कर ली गई है, जो कि दलहन फसलों की बोनी के लिये निर्धारित लक्ष्य का 94 प्रतिशत है।
- इसी प्रकार राज्य में अब तक तिलहनी फसलों की बुआई 2.84 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अलसी की बुआई 46 हज़ार 190 हेक्टेयर में, राई सरसों की 2 लाख हेक्टेयर में, तिल की 1370 हेक्टेयर में, सूरजमुखी 2960 हेक्टेयर, कुसुम की 6960, मूंगफली की 25,630 तथा अन्य तिलहनी फसल की बोनी 160 हेक्टेयर में पूरी हो चुकी है, जो कि तिलहन फसलों की बोनी के लक्ष्य का 75 प्रतिशत है।

बीमार एवं बंद उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू

चर्चा में क्यों ?

10 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीमार एवं बंद उद्योगों के लिये निवेश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योग के लिये नई नीति लागू की है। इससे बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पाएंगे।
- इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि सहित अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति-2022
- राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने, देश के कुल निर्यात में राज्य का योगदान बढ़ाने, राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में कृषि को प्रोत्साहित करने एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2022 (01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024) लागू की गई है।
- इस नीति के तहत लॉजिस्टिक, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, स्वयं सहायता समूह तथा कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किये जाने पर औद्यौगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है।
- इस नीति के अंतर्गत उद्यमों में किये गये स्थायी पूंजी निवेश का 35-55 प्रतिशत तक अधिकतम राशि रुपए 35-350 लाख तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, 50-60 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपए 10-55 लाख तक ब्याज अनुदान, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5-8 वर्ष तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट, स्टॉम्प शुल्क से छूट तथा परिवहन वाहन अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

- छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति
- वर्तमान में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। प्रदेश में जितनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इन स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार एवं बंद भी हुए हैं।
- इन बीमार व बंद उद्योगों को पुन: संचालित किये जाने, पुन: रोज़गार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है।
- इसके तहत् बीमार एवं बंद उद्योगों के पुर्नवास और पुर्नसंचालन पैकेज अंतर्गत स्टांप शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नि:शक्त अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मंडी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान है।

नये कलेवर में वेब मीडिया 'सीजीवालडॉटकॉम' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में नये कलेवर में वेब मीडिया 'सीजीवालडॉटकॉम' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजीवाल लंबे समय से छत्तीसगढ़ के समाचारों को आम जनता तक पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा कि सीजीवाल समाचार भी है, विचार भी है और संवाद भी, अब यह एक नए कलेवर में जनता के सामने आ रहा है।
- सीजीवाल के प्रमुख संपादक रुद्र अवस्थी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2014 से संचालित वेब मीडिया सीजीवालडॉटकॉम एक भरोसेमंद प्लेटफार्म है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों से संबंधित खबरें लगातार प्रसारित की जा रही हैं।
- अब इस वेब मीडिया को आकर्षक पेज के साथ एक बार फिर नया कलेवर दिया गया है, जिससे अधिक तेजी से खबरें पाठकों तक पहुँच सकेंगी।
- नए कलेवर में पाठकों को विभिन्न क्षेत्रों की खबरें अलग-अलग कैटेगरी में सुविधाजनक ढंग से मिल सकेंगी।

जल जीवन मिशन: राज्य में 21.20 लाख से अधिक परिवारों को मिला घरेलू नल कनेक्शन

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिये चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 21 लाख 20 हज़ार 616 घरेलू नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

प्रमुख बिंदु

- घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के साथ-साथ राज्य के 43 हज़ार 942 स्कूलों, 41 हज़ार 676 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17 हज़ार 286 ग्राम पंचायत भवनों और सामुदायिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके लिये सभी ज़िलों में कार्ययोजना तैयार कर तेजी से कार्य किये जा रहे हैं।
- इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप-स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है।
- जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर-चांपा जिले में सबसे अधिक 1 लाख 83 हज़ार 377 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। दुसरे स्थान पर राजनांदगाँव ज़िला है जहाँ अब तक 1 लाख 53 हज़ार 811 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
- जल जीवन मिशन के तहत रायपुर ज़िले में 1 लाख 26 हज़ार 655, रायगढ़ में 1 लाख 20 हज़ार 575, धमतरी में 1 लाख 16 हज़ार 133, बलौदाबाज़ार-भाटापारा में 1 लाख 2 हज़ार 407, कवर्धा में 1 लाख 522, महासमुंद में 97 हज़ार 559, बिलासपुर में 92 हज़ार 634, बेमेतरा में 91 हज़ार 191, दुर्ग में 90 हज़ार 600 और मुंगेली ज़िले में 83 हज़ार 141 नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
- इसी तरह बालोद ज़िले में 82 हज़ार 508, गरियाबंद में 70 हज़ार 775, जशपुर में 61 हज़ार 034, कांकेर में 60 हज़ार 364, बस्तर में 58 हज़ार 253, कोरबा में 57 हज़ार 482, बलरामपुर में 57 हज़ार 154, सरगुजा में 55 हज़ार 884, सूरजपुर में 54 हज़ार 390, कोरिया में 52 हज़ार 769, कोण्डागांव में 51 हज़ार 399, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 24 हज़ार 672, बीजापुर में 21 हज़ार 569, सुकमा में 20 हज़ार 686, दंतेवाड़ा में 19 हज़ार 779 और नारायणपुर ज़िले में 13 हज़ार 293 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
- उल्लेखनीय है कि 'जल जीवन मिशन' की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। मिशन के तहत 2024 तक देश के सभी दूर-सुदूर गाँवों के हर घर तक शुद्ध पेय जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। यह मिशन पेय जल को आम लोगों तक आसानी से पहुँचाने के साथ-साथ दीर्घ कालिक जल स्रोतों का निर्माण, जल संरक्षण, प्रदूषण रहित जल की पहचान, जल प्रबंधन आदि की कार्य योजना पर कार्य करता है।
- विदित है कि इस मिशन की घोषणा के वक्त देश में 19.27 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में ही नल से जल मुहैया हो रहा था लेकिन पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुँचाने के अभियान में अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसी का नतीजा है कि अब 11 करोड़ घरों में नल से जल पहुँचने लगा है।
- देश में पाँच राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों ने 100 प्रतिशत हर घर नल से जल पहुँचाने में सफलता हासिल कर ली है। इन पाँच राज्यों में हरियाणा, गोवा, तेलंगाना, गुजरात और पंजाब शामिल हैं जबकि तीन केंद्रशासित प्रदेशों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव और दादर नागर हवेली और पुदुच्चेरी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर के लाल बाग में आयोजित 'भरोसे का सम्मलेन' में विशिष्ट अतिथि प्रियंका गांधी की उपस्थिति में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामय आयोजन के लिये राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- योजना के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग के 1840 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपए की अनुदान राशि जारी की।
- इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष दो किश्तों में 10 हज़ार रुपए की राशि मिलेगी।
- योजना का उद्देश्य:
    - 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' के तहत अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में जनजातियों के उत्सवों, त्यौहारों के मेला, मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली आदि उत्सवों, त्यौहारों, संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की अनुदान राशि दो किश्तों में जारी की जाएगी।

नोट :

- मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि का उद्देश्य आदिवासियों के तीज त्यौहारों की संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करना एवं इन त्यौहारों, उत्सवों को मूल स्वरूप में आगामी पीढ़ी को हस्तांतरण तथा सांस्कृतिक परंपराओं का अभिलेखन करना है।

- योजना का क्रियान्वयन: योजना की इकाई ग्राम (गाँव) होंगे। योजना के लिये नोडल एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत होंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम स्तरीय शासी निकाय एवं अनुभाग स्तरीय शासी निकाय का गठन किया जाएगा। निकाय का स्वरूप निम्नानुसार होगा-
- ग्राम स्तरीय शासी निकाय में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच अध्यक्ष होंगे। गायता, पुजारी, सिरहा, गुनिया, बैगा सदस्य होंगे। ग्राम स्तरीय शासी निकाय में ग्राम के दो बुजुर्ग, दो महिला, ग्राम कोटवार, पटेल और ग्राम पंचायत के सचिव सदस्य होंगे।
- जनपद स्तरीय शासी निकाय में अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अध्यक्ष होंगे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत इसके सदस्य सचिव होंगे। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार इसके सदस्य होंगे।
    - ग्राम में कौन-कौन से त्यौहारों में इस राशि का उपयोग किया जाना है इसका निर्धारण ग्राम स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी एवं समन्वय हेतु जनपद स्तरीय शासी निकाय उत्तरदायी होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की संस्कृति और पर्वों की परंपरा के संरक्षण के लिये 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' की घोषणा की थी।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इस योजना के लिये 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना छत्तीसगढ़ के समस्त अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजाति विकासखंड) में लागू होगी।

पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

चर्चा में क्यों?

14 अप्रैल, 2023 को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर एवं सफल क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में भारत सरकार के सचिव मनोज आहूजा ने छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र सौंपा।

राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल की स्वचलित गणना और निपटान के लिये डिजीक्लेम मॉड्यूल का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही पोर्टल दर्ज करने और बीमा का लाभ किसानों तक पहुँचाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की गई है।

छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 6 लाख 77 हज़ार 558 पात्र किसानों को फसल बीमा का लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192.41 करोड़ रुपए की राशि दी गई है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश भर में अग्रणी राज्यों में शुमार है।

उप स्वास्थ्य केंद्र खजुरी को प्रदेश भर में मिला प्रथम स्थान

चर्चा में क्यों?

13 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव की उपस्थिति में रायपुर में 'कायाकल्प योजना' वर्ष 2022-23 के अंतर्गत पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र खजूरी को प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- 'कायाकल्प योजना' के तहत स्वास्थ्य विभाग तथा सहयोगी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारिओं की ओर से स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं के आधार पर अंक प्रदान किये जाते हैं।

- इस क्रम में ज़िले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र खजुरी को पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया।
- इसके अलावा ज़िले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रनहत को भी सराहना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

कायाकल्प योजना के अंतर्गत सूरजपुर ज़िले को मिला प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2022-23 में उप स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में उप स्वास्थ्य केंद्र जूर विकासखंड भैयाथान को प्रथम पुरस्कार तथा उप स्वास्थ्य केंद्र डेडरी विकासखंड सूरजपुर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 81 स्वास्थ्य संस्थाओं को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया।
- उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले अस्पताल को 1,00000 एवं द्वितीय पुरस्कार के विजेता अस्पताल को 50,000 की राशि प्रदान की गई।
- वहीं वर्ष 2021-22 में राज्य में प्रथम स्थान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नवापारा कला विकासखंड प्रेमनगर को एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसदेई को पुरस्कृत किया गया था।
- यह पुरस्कार बेहतर प्रबंधन बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनता तक पहुँचाने एवं साथ ही अस्पतालों में स्वच्छता के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट कार्य करने पर ज़िले से सुश्री शुभम श्रीवास्तव को राज्य में सर्वश्रेष्ठ आरएमएनसीएच ए का पुरस्कार दिया गया। वहीं डॉ. तेरस कंवर नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दीपक मरकाम डेंटल सर्जन को भी उत्कृष्ट कार्य करने हेतु पुरस्कृत किया गया।

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले का सीएचसी जनकपुर स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन में प्रदेश में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में रायपुर में आयोजित समारोह में मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ज़िले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को स्वच्छता व बेहतर प्रबंधन हेतु राज्य में पहला स्थान हासिल करने पर प्रमाणपत्र व शील्ड से सम्मानित करते हुए पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए का चेक प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार कायाकल्प योजना अंतर्गत 2022 -23 हेतु प्रदान किया गया।
- नवगठित ज़िला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर को शासकीय अस्पतालों में सफाई प्रबंधन, रोग नियंत्रण, भवन एवं परिसर सौंदर्यीकरण, रोग सेवा में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन, स्वच्छ अस्पताल योजना में किये गए कार्यों के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर की अधोसंरचना प्रदेश के निजी अस्पताल के अनुकूल है। एमसीबी ज़िले के अलावा अन्य राज्य जैसे एमपी के मरीज भी इस अस्पताल मे सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।
- यहाँ मरीजों को गुणवत्तापूर्ण ईलाज तो दिया ही जाता है साथ ही मरीजों के लिये गुणवत्तापूर्ण नि:शुल्क आहार, जैव अपशिष्ट का त्वरित निपटान, ज़िले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों के लिये एक प्रेरणा का स्रोत है।
- यहाँ मरीजो एवं स्टाफ को संक्रमण से बचाने के लिये अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली बेहतरीन है।

नोट :

कबीरधाम ज़िले के पाँच स्वास्थ्य संस्थानों को मिला कायाकल्प पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 अप्रैल, 2023 को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तत्वावधान में रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कबीरधाम ज़िले के पाँच स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प योजना का पुरस्कार प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2022-23 के अंतर्गत ज़िले के पाँच स्वास्थ्य संस्थान ज़िला अस्पताल कबीरधाम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर्धा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इंदौरी एवं मडमड़ा उप स्वास्थ्य केंद्रों (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) को कायाकल्प पुरस्कार से पुरस्कृत किया है।
- कबीरधाम ज़िले को यह पुरस्कार वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के विभिन्न मापदंडों में छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल करने और कायाकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई प्रबंधन, रोग संक्रमण नियंत्रण, भवन एवं परिसर, सौंदर्यकरण, रुग्ण सेवा में सुधार, के लिये समयबद्ध कार्यक्रम, घोषित आंतरिक मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन एवं बाह्य मूल्यांकन की कसौटी को पूरा करने पर प्रदान किया गया है।

केरता शक्कर कारखाना के नवनिर्मित को-जनरेशन पॉवर प्लांट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में को-जनरेशन पॉवर प्लांट के विद्युत उत्पादन कार्य का स्टार्ट बटन दबाकर विधिवत शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- को-जनरेशन प्लांट के शुभारंभ के साथ ही माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। इस प्लांट में 2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन को-जनरेशन प्लांट के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिससे कारखाने के साथ-साथ किसानों को भी फायदा होगा।
- माँ महामाया शक्कर कारखाना को विद्युत उत्पादन से हर महीने लगभग एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अनुमानित है।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि इस प्लांट के प्रारंभ होने से कारखाना और किसान दोनों को लाभ होगा। कारखाना में सरप्लस बिजली का उपयोग नही हो रहा था, जिसे ध्यान मे रख पॉवर प्लांट की स्थापना के लिये सरकार ने 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, जिससे प्लांट की स्थापना की गई।
- यहाँ एथेनॉल प्लांट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कारखाना प्रबंधन को महाराष्ट्र के समृद्ध शक्कर कारखानों का भ्रमण अवलोकन वहाँ की प्रबंधन एवं तकनीक को केरता कारखाने में भी लागू करने का सुझाव दिया ताकि यह शक्कर कारखाना किसानों के लिये और अधिक लाभप्रद हो सके।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के साथ किसान हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में गन्ना, धान, तेंदूपत्ता का सर्वाधिक दाम दिया जा रहा है। वहीं 65 प्रकार का वनोपज और मिलेट्स की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जा रही है।
- मंत्री डॉ. टेकाम ने बताया कि राज्य सरकार जनवरी माह में कवर्धा के शक्कर कारखाना में एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ करने जा रही है।
- उन्होंने बताया कि इस वर्ष यहाँ पर शक्कर कारखान के रिकवरी 9 प्रतिशत रही, अगर 10 प्रतिशत से ऊपर शक्कर की रिकवरी हो, तो इसका लाभ किसानों को मिलेगा।

राष्ट्रपति ने प्रदेश के दो पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया

चर्चा में क्यों?

17 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की दो ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- धमतरी ज़िले के नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सांकरा को तथा सरगुजा ज़िले के लूंड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत नगम को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है।
- ग्राम पंचायत सांकरा को यह पुरस्कार 'स्वस्थ पंचायत' की श्रेणी में जबकि ग्राम पंचायत नगम को 'गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत' की श्रेणी में प्रदान किया गया है।
- विदित है कि दीनदायाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयू पीएसवीपी) के तहत स्वस्थ पंचायत श्रेणी में स्वास्थ्य संबंधी उत्कृष्ट कार्यों के लिये जनपद पंचायत नगरी की सर्वाधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत सांकरा छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पर रही।
- उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सांकरा को इसके पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार से भी नवाज़ा जा चुका है।
- निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में चुनी गईं पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये गए-
  - व्यक्तिगत एलएसडीजी विषय वस्तुओं के तहत प्रदर्शन के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)
  - सभी 9 एलएसडीजी विषयों और हरित पहल से संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिये नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (एनडीएसपीएसवीपी)
  - ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार
  - कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार।

राज्य फाइनल: वर्ड पावर चैंपियनशिप -2023

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिये वर्ड पावर चैंपियनशिप (WPC) राज्य फाइनल में विजेता रहे शीर्ष दो विजेताओं को मुंबई में 28 अप्रैल को होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि छत्तीसगढ़ के लिये वर्ड पावर चैंपियनशिप (WPC) राज्य फाइनल का आयोजन 11 अप्रैल को न्यू सर्किट हाउस में किया गया था।
- कक्षा- 4 की राज्य वर्ड पावर चैंपियनशिप के विजेता शासकीय प्राथमिक शाला, ज़िला-रायगढ़ की कुमारी नंदिनी चौहान, कक्षा-5वीं की विजेता ज़िला-धमतरी के मयंक कुमार निषाद और उपविजेता उपासना साहू, कक्षा-4, ज़िला-रायपुर एवं गरिमा साहू, कक्षा-5वीं, ज़िला-दुर्ग रहे।
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के संचालक राजेश सिंह राणा ने कहा की 'वर्ड पावर चैंपियनशिप' एक सराहनीय पहल है जो छात्रों की झिझक दूर कर अंग्रेजी भाषा कौशल को प्रदर्शित करने के लिये मंच प्रदान करता है। इस तरह की प्रतियोगिताएँ न केवल अंग्रेजी भाषा के प्रति छात्रों की रुचि को बढ़ाती है बल्कि छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित करती है।
- राज्य फाइनल का आयोजन लीपफॉरवर्ड, मुंबई स्थित एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन द्वारा निहार शांति पाठशाला फनवाला (एनएसपीएफ) और एससीईआरटी, छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया गया।

नोट :

- वर्ड पावर चैंपियनशिप एक वार्षिक कार्यक्रम है जो उन छात्रों एवं शिक्षकों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है जिन्होंने LeapForWord के अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
- प्रतियोगिता में सभी ज़िलों से कक्षा चौथी और पाँचवी के 34,071 बच्चों ने पंजीकरण कराया था। वर्ड पावर चैंपियनशिप हिन्दी माध्यम विद्यालयों के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता है। राज्य फाइनल में क्लस्टर, ब्लॉक और ज़िला स्तर के राउंड के बाद, 9 बच्चे इवेंट के स्टेट फिनाले में पहुँचे।
- छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों से कक्षा चौथी और पाँचवीं दोनों कक्षाओं हेतु पृथक-पृथक प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। कक्षा चौथी में शब्द के स्पेलिंग एवं रीडिंग एवं कक्षा पाँच स्पेलिंग, रीडिंग एवं मीनिंग से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।
- राज्य फाइनल प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को एक सैमसंग टैबलेट, साइकिल और स्कूल किट उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। साथ ही उनके स्कूलों को टॉवर स्पीकर और स्पोर्ट्स किट से सम्मानित किया गया।
- कार्यक्रम में उन शिक्षकों को भी प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया गया जिन्होंने इन छात्रों को इस मुकाम तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया। इसी प्रकार उपविजेता छात्रों को साइकिल एवं स्कूल किट से पुरस्कृत किया गया तथा उनके विद्यालयों को खेल किट भेंट किया गया।

मुख्यमंत्री ने किया हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान रायपुर के हीरापुर जरवाय में सी एंड डी प्लांट का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होने से तोड़फोड़ एवं अन्य प्रक्रियाओं से निकलने वाले निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट जिसे आम बोलचाल की भाषा में मलबा कहते हैं, इनके उचित प्रबंधन के लिये सी एंड डी प्लांट का निर्माण किया गया है।
- इस सी एंड डी प्लांट पर मलबों की प्रोसेसिंग कर पेवर ब्लॉक, टाइल्स, ड्रेन कवर इत्यादि का निर्माण किया जाएगा।
- सी एंड डी प्लांट के जरिये मलबों के उचित समायोजन से वायु की गुणवत्ता, नालों के प्रवाह में अवरोध तथा तालाबों के जल संचयन की क्षमता में कमी आने जैसी समस्याओं में कमी आएगी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों के लिये 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि' योजना का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सामुदायिक विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के तीज त्यौहार, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि'योजना का वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ग्रामीण क्षेत्रों के तीज-त्यौहारों, संस्कृति एवं परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से यह योजना 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि'योजना की तर्ज पर शुरू की गई है।
- विदित है कि इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के विशिष्ट आतिथ्य में बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बीते 13 अप्रैल को आयोजित भरोसा सम्मेलन में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि'योजना की शुरुआत की थी।
- 'मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना'राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के सामुदायिक क्षेत्रों के 61 विकासखंड की 6 हज़ार 111 ग्राम पंचायतों में लागू होगी।
- इस योजना की इकाई ग्राम पंचायत होगी। तीज-त्यौहार मनाने के लिये इस योजना में भी हर ग्राम पंचायत को दो किश्तों में 10 हज़ार रुपए की राशि दी जाएगी।

नोट :

- सामुदायिक क्षेत्रों के गाँवों में स्थानीय उत्सवों, त्यौहारों, मेला-मड़ई का विशेष महत्व रहता है। ऐसे सभी उत्सवों, त्यौहारों, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत को राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
- योजना के क्रियान्वयन के लिये ग्राम पंचायत स्तरीय शासी निकाय समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सरपंच (अध्यक्ष), पुजारी, बैगा सदस्य, ग्राम के 2 बुजुर्ग सदस्य, ग्राम की दो महिला सदस्य, ग्राम कोटवार, पटेल सदस्य एवं ग्राम सचिव को शामिल किया गया है।
- मुख्यमंत्री ने योजना के शुभारंभ अवसर पर योजना की पहली किश्त के रूप में सभी 6 हज़ार 111 ग्राम पंचायतों को 05-05 हज़ार रुपए के मान से कुल 3 करोड़ 5 लाख 55 हज़ार रुपए की राशि जारी की।
- मुख्यमंत्री ने इसके साथ-साथ 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि' के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के सरगुजा संभाग सहित अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के शेष 14 ज़िलों की 03 हज़ार 793 ग्राम पंचायतों को प्रथम किश्त के रुप में 05-05 हज़ार रुपए के मान से कुल 01 करोड़ 89 लाख 65 हज़ार रुपए की राशि भी जारी की। इसके साथ ही यह योजना पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बघेल ने 13 अप्रैल को बस्तर में आयोजित भरोसा सम्मेलन में 'मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना' का शुभारंभ करते हुए बस्तर संभाग की 1840 ग्राम पंचायतों को योजना की पहली किश्त के रूप में 5-5 हज़ार रुपए के मान से अनुदान राशि जारी की थी।

मुख्यमंत्री ने 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों को 4.40 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 'गोधन न्याय योजना' के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 4.40 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किये गए कुल 1.30 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 2.59 करोड़ रुपए, गौठान समितियों को 1.06 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 75 लाख रुपए की लाभांश राशि ऑनलाईन अंतरित की।
- गोबर विक्रेताओं को अंतरित की गई 2.59 करोड़ रुपए की राशि में से 1.24 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 1.67 करोड़ रुपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है।
- गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक लगभग 439 करोड़ 73 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- राज्य में 15 अप्रैल, 2023 तक गौठानों में 112.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से आज की राशि अंतरण के पश्चात् क्रय किये गए गोबर के एवज में 224 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को आज किये गए 1.81 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद 192.65 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है।
- गौरतलब है कि प्रदेश की 11 हज़ार पंचायतों में 10 हज़ार 6 सौ नब्बे गौठान स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 10 हज़ार से अधिक गौठान पूर्ण हो गए हैं। इन गौठानों में 5 हज़ार 3 सौ 98 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं, जिनके द्वारा गोबर खरीदने के लिये 50 करोड़ 82 लाख रुपए की सहायता दी गई है।

- प्रदेश के 49 गौठानों में गोबर से पेंट तैयार करने की इकाई स्वीकृत की गई है जिसमें से 34 इकाईयाँ की स्थापना की जा चुकी है। 32 इकाई में पेंट का उत्पादन किया जा रहा है। इन इकाईयों से 87 हज़ार 8 सौ 27 लीटर पेंट की उत्पादन किया गया है तथा 47 हज़ार 5 सौ 47 लीटर पेंट के बिक्री से 97.08 लाख रूपये की आय अर्जित की गई है।
- राज्य के 33 ज़िलों के गौठानों में 20.20 लाख क्विंटल पैरा और 7 हज़ार 8 सौ 59 गौठानों में पानी की व्यवस्था की गई है।

शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर के 41 अस्पतालों को मान्यता

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिये राज्य के बाहर स्थित 41 अस्पतालों को मान्यता दी है।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी की है।
- शासकीय कर्मियों के इलाज के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये इन अस्पतालों को मान्यता मिली है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार के लिये विगत 11 अप्रैल को 92 अस्पतालों की सूची जारी की थी जिनमें प्रदेश के विभिन्न शहरों के 91 और राज्य के बाहर स्थित एक अस्पताल नीति क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रामदासपेठ, नागपुर शामिल था।
- विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में राज्य के बाहर स्थित 40 अस्पताल शामिल हैं। इस तरह शासकीय सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों की कुल संख्या अब 132 हो गई है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तो और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।

मानस मंडलियों की महिलाओं को मिलेगा माता कौशल्या अलंकरण

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने चंदखुरी में आयोजित माता कौशल्या महोत्सव की औपचारिक शुरुआत करते हुए अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही मानस मंडलियों की महिलाओं को माता कौशल्या अलंकरण दिये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 तक आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित किये जा रहे माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया।
- माता कौशल्या अलंकरण महिला सशक्तीकरण के लिये राज्य शासन की विशेष पहल है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में सतत् प्रयास के अंतर्गत तथा माता कौशल्या जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तीकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत् विकास हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने की घोषणा की थी।

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'स्टेट्स ऑफ वूमेन' पुस्तक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने रायपुर के सर्किट हाउस में श्रीमती आभा प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक 'स्टेट्स ऑफ वूमेन' का विमोचन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने कहा कि 'स्टेट्स ऑफ वूमेन' किताब में महिलाओं से संबंधित कानून, प्रक्रिया और नियमों का उल्लेख किया गया है, जिसकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिये।
- पुस्तक की लेखिका डॉ. आभा प्रसाद ने कहा कि अधिकांश महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता है। 'स्टेट्स ऑफ वूमेन' में महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों का समावेश किया गया है, जिससे उन्हें एक पुस्तक में सभी अधिकारों की जानकारी मिल सके।

खनिजों से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में मिला रिकार्ड 12 हज़ार 941 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में संचालित खनिज गतिविधियों से 12 हज़ार 941 करोड़ रुपए का रिकार्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है।

प्रमुख बिंदु

- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म जय प्रकाश मौर्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में मुख्यत: कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट खनिजों से राजस्व प्राप्त होता है।
- लौह अयस्क से सर्वाधिक 3607 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। खनिज कोयले से 3336 करोड़ रुपए, चूना पत्थर से 392 करोड़ रुपए एवं बॉक्साइट से 31 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति के ज़िलों में दंतेवाड़ा से 6419 करोड़, कोरबा से 2361 करोड़, रायगढ़ से 1717 करोड़, बालोद से 760 करोड़, बलौदाबाज़ार से 315 करोड़, कांकेर से 286 करोड़ एवं सरगुजा ज़िले से 262 करोड़ रुपए खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई है।
- प्रदेश में प्राप्त होने वाले खनिज जहाँ राज्य में अधोसंरचनात्मक विकास, बिजली के उत्पादन, उद्योगों के संचालन में अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं खनिज राजस्व राज्य के वित्तीय विकास में महत्त्वपूर्ण साझेदारी प्रदान कर रहा है।
- विभाग के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन की नवीन नीति के तहत वर्ष 2015-16 में ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित 02 मुख्य खनिज चूना पत्थर ब्लॉक्स यथा करही चंडी, ज़िला बलौदाबाज़ार-भाटापारा एवं केसला, ज़िला रायपुर में वर्ष 2022-23 में उत्पादन प्रारंभ हुआ है।

छत्तीसगढ़ मास्टर्स टेबल टेनिस टीम की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 23 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ वेटरन टेबल टेनिस कमेटी ने जालंधर में शुरू हो रही 29वीं नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिये राज्य की टीम की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 29वीं नेशनल मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 30 अप्रैल तक जालंधर में हो रहा है।
- छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने बताया कि प्रत्येक वर्ग में खिलाड़ियों का चयन किया गया है।
- घोषित टीम के खिलाड़ी हैं:
  - आयु वर्ग 40: पुरुष- निखिल बानी (रायपुर), महिला- शिखा खांडे हुसैन (बिलासपुर)
  - आयु वर्ग 50 (क): पुरुष- राजेश अग्रवाल, कप्तान (रायपुर), संजय लहेजा (बिलासपुर), सुरेश शादिजा (रायपुर), रितेश मल्होत्रा (रायपुर)

नोट :

- आयु वर्ग 50 (बी): पुरुष- अरविंद कुमार शर्मा, कैप्टन (रायपुर महानगर), गिरिराज बागड़ी (रायपुर), विधानदीप मिश्रा (रायपुर), विनय केजरीवाल (रायपुर महानगर)।
- आयु वर्ग 60: पुरुष- पवन शादीजा, कैप्टन (रायपुर), शेन स्टीफेन (रायपुर), सुशांत बोरवंकर (रायपुर), के. रविशंकर (बिलासपुर), जे.एम. राठौड़ (रायपुर महानगर)।
- आयु वर्ग 65: पुरुष- प्रदीप जनवाडे, कप्तान (रायपुर), आर.एन. केलकर (दुर्ग), ए.एन. राव (बिलासपुर)
- आयु वर्ग 65: महिला- गौरी डे, कप्तान (बिलासपुर), इरा पंत (रायपुर), सरबरी मोइत्रा (बिलासपुर)।
- टीम के कोच रविशंकर (बिलासपुर) तथा मैनेजर अरविंद कुमार शर्मा (रायपुर महानगर) हैं। राज्य से अजीत बनर्जी (रायपुर) और जया साहू (राजनांदगाँव) अंपायर होंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उल्लेखनीय कार्य के लिये छत्तीसगढ़ हुआ पुरस्कृत

चर्चा में क्यों?

- 25 अप्रैल, 2023 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिये राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ (State Urban Development Agency (SUDA) को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया।
- दिल्ली में आयोजित इस समारोह में सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा राज्य के समस्त 33 ज़िलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख 62 हज़ार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें अब तक 1 लाख 40 हज़ार घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिये आवास मिशन के क्रियान्वयन में अद्यतन लगभग 42 सौ करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों को केंद्र सरकार ने किया पुरस्कृत
  - आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण हेतु अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।
  - योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।
  - शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण हेतु ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।
  - 'मोर मकान-मोर आस' योजना में समूह आवासों के माध्यम से किराये में निवासरत शहरी गरीबों को योजना में शामिल करने का अभूतपूर्व निर्णय शासन द्वारा लिया गया। इससे शहरी क्षेत्रों के लगभग 25 से 30 हज़ार आवासहीन किरायेदारों को आवास प्रदान किया जा रहा है।
  - नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को लाभ - राज्य द्वारा नगर पंचायत, अंतागढ़ में नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित 80 परिवारों के हितग्राहियों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।
- सबके लिये आवास (शहरी) अंतर्गत पूर्व में प्राप्त पुरस्कार-
  - भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 के अंतर्गत Best State for Convergence with Other Missions में नगर निगम राजनांदगाँव, नगर पंचायत अंतागढ़ एवं नगर पंचायत गंडई को पुरस्कार प्रदान किया गया।
  - भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया।

नोट :

- HUDCO Award 2019-2020 में नगर निगम राजनांदगाँव को हाउसिंग, अरबन पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया।
- भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC) 2022 में PMAY Award, 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022 में PMAY Awards, 2021 में नगर पंचायत पाटन को बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

24 अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) के संचालक पी.सी. मिश्रा ने छत्तीसगढ़ में पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस (Panchayati Raj Institutions-Community Based Organisation Convergence) परियोजना का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना के तहत गाँवों में आजीविका के अवसर बढ़ाने और गरीबी कम करने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के सामुदायिक संगठनों और ग्राम पंचायतों के अभिसरण (Convergence) से मिशन के अंतर्गत गठित स्वसहायता समूहों को उद्यमशील बनाया जाएगा।
- पीआरआई-सीबीओ कन्वर्जेंस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीबी को कम करने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिये संकुल संगठन, ग्राम संगठन तथा स्वसहायता समूह जैसे स्थायी समुदाय आधारित संगठनों को बढ़ावा देकर ग्राम पंचायतें और स्वसहायता समूहों के संघ अभिसरण से काम करेंगी।
- इसके तहत समुदाय के भीतर सेवा वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिये स्थानीय सरकार और लाइन विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों और लाइन विभागों के साथ सीबीओ नेटवर्क भी बनाया जाएगा।
- यह परियोजना बस्तर ज़िले के बकावंड, बास्तानार, लोहंडीगुड़ा और तोकापाल विकासखंडों तथा रायपुर ज़िले के अभनपुर, आरंग, धरसीवा और तिल्दा विकासखंड के कुल 200 ग्राम पंचायतों में संचालित की जाएंगी।
- इसमें इन सभी विकासखंडों की 25-25 ग्राम पंचायतों के 'बिहान'के कुल 32 संकुल संगठनों और 640 ग्राम संगठनों सहित इनसे जुड़ी स्वसहायता समूह हिस्सेदारी करेंगी।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (CCO) श्रीमती एलिस लकड़ा ने कार्यशाला में बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं एवं 'बिहान'के अंतर्गत गठित सामुदायिक संगठनों के बीच बेहतर सांमजस्य से गाँवों के विकास के लिये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) के 17 संकेतकों का क्षेत्रीकरण कर उन्हें नौ थीमों में वर्गीकृत किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पहले ज़ीरो वेस्ट, अत्याधुनिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में भेंट-मुलाकात के दौरान भाठागाँव में 80 एमएलडी क्षमता का छत्तीसगढ़ का पहला ज़ीरो वेस्ट, अत्याधुनिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये नगर निगम रायपुर के 9 बैक हो लोडर गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र लगभग 15 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है।
- इस संयंत्र का संचालन लैमेला ट्यूब सेटलर पद्धति से किया जाएगा। यह पूरी तरह से स्वचलित प्रणाली पर आधारित है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित जल शोधन संयंत्र के संचालन की पूरी प्रक्रिया और तकनीकी जानकारियाँ ली और कंट्रोल रूम का अवलोकन भी किया। इस मौके पर भी उन्होंने भाठागाँव में ही दो पुराने जल शोधन संयंत्रों के उन्नयन के बाद इसे लोकार्पित किया। इन पुराने जल शोधन संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई गई है।
- नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नवनिर्मित जल शोधन संयंत्र से राजधानी रायपुर को टैंकरमुक्त कर पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही पुराने शोधन यंत्रों के आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार से भी राजधानी टैंकरमुक्त हो सकेगी।
- भाठागाँव में पहले से स्थापित 150 एमएलडी के फील्टर प्लांट में भी क्षमता बढ़ाने के लिये छह नये मोटर पंप लगाए गए है। इन नये मोटर पंपों से 1706 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा पानी देने वाले संयंत्र की क्षमता बढ़कर 2046 क्यूबिक मीटर प्रतिघंटा हो गई है। इसी तरह 80 एमएलडी के पुराने फील्टर प्लांट में भी छह नये मोटर स्थापित किये गए है। इस संयंत्र की क्षमता 954 से बढ़कर 995 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हो गई है।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल पुस्तक का किया विमोचन

चर्चा में क्यों?

26 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने पुस्तक के प्रकाशन पर ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और हथकरघा संघ की प्रबंध संचालक रेखा शुक्ला को बधाई दी और कहा कि यह कॉफी टेबल पुस्तक छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के प्रचार-प्रसार में बहुत उपयोगी साबित होगी।
- प्रबंध संचालक रेखा शुक्ला ने बताया कि इस पुस्तक का नाम 'मंगठा' रखा गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को 'मंगठा' भी कहते हैं।
- इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में बुने जाने वाले कोसा, खादी और कॉटन की साड़ियों की निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी और विभिन्न प्रकार की साड़ियों को सुंदर चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है।
- यह पुस्तक छत्तीसगढ़ के हैंडलूम बुनकरों को समर्पित है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ हैंडलूम के प्रचार-प्रसार में इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा।

नोट :